Panchayati Raj Institutions (PRIs)

पंचायती राज संस्थाएँ

Rajasthan (Nagaur) 1959

1952 – CDP (Community Development program)

← 1957 – CDP review

Balwant rai Mehta Committee.

PRS

DC

District

BDO

Block

VDO

Village

Zila Panchayat

Panchayat Samiti

Village Panchayat

Direct

Panchayati Raj Institutions (PRIs)

- Panchayati Raj Institutions (PRIs) refer to the system of 'Rural Local Self-Governance' in India i.e. a system of governance of Rural Areas through the representatives elected by the people./ पंचायती राज संस्थान (PRI) भारत में 'ग्रामीण स्थानीय स्वशासन' की प्रणाली को कहते हैं, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का शासन करने की प्रणाली।

- They have been established in all States as the third tier of government, aiming to build democracy at the grassroots level./ इन्हें सभी राज्यों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है।

- It was constitutionalised through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992./ इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

Evolution of Panchayati Raj / पंचायती राज का विकास

Balwant Rai Mehta Committee / बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- The first such committee was the Balwantrai Mehta Committee, appointed by the Government of India in 1957./ पहली ऐसी समिति बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसे भारत सरकार ने 1957 में नियुक्त किया था।
- To examine the working of the Community Development Programme (1952) and the National Extension Service (1953)./ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (1952) और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस (1953) के कामकाज की जांच करना।
- Establishment of a three –tier panchayati raj system – gram panchayat at the village level, panchayat samiti at the block level and zila parishad at the district level./ तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना - गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
- These tiers should be organically linked through a device of indirect elections./ ये स्तर अप्रत्यक्ष चुनावों के ज़रिए आपस में जुड़े होने चाहिए।
- The village panchayat should be constituted with direct elections/ ग्राम पंचायत का गठन सीधे चुनावों से होना चाहिए।

Evolution of Panchayati Raj / पंचायती राज का विकास

- Panchayat Samiti and Zilla Parishad: constituted with indirectly elected/ पंचायत समिति और जिला परिषद: अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से गठित।
- Chairman of the Zilla Parishad: District collector/ जिला परिषद का अध्यक्ष: जिला कलेक्टर
- Based on the recommendations of the Balwantrai Mehta Committee, most of the states in India established PRIs by the mid-1960s./ बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत के ज़्यादातर राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक PRIs की स्थापना की।
- Rajasthan was the first state in India to establish PRIs in the year 1959./ राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने 1959 में PRIs की स्थापना की।
- Andhra Pradesh was the second state in India to establish PRIs in the same year 1959/ आंध्र प्रदेश उसी साल 1959 में PRIs स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य था।

Ashok Mehta committee (1977)

- In December 1977, the Janata Government appointed a committee on Panchayati Raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta./ दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की।
- It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations./ इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 132 सिफारिशें कीं।
- Three-tier system of Panchayati raj should be replaced by the two-tier system – zilla parishad and mandal panchayat (consisting of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000)/ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली को दो-स्तरीय प्रणाली - जिला परिषद और मंडल पंचायत (15,000 से 20,000 की कुल आबादी वाले गांवों के समूह से मिलकर) से बदल दिया जाना चाहिए।
- District as first point for decentralisation under popular supervision below the state level./ राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिले को पहला बिंदु बनाया जाए।

Ashok Mehta committee (1977)

- Official participation of political parties at all levels of panchayat elections./ पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी।
- Compulsory powers of taxation to PRIs to mobilise own financial resources./ अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए PRIs को अनिवार्य कराधान शक्तियां दी जाएं।
- Regular social audit by a district level agency and by a committee of legislators to ascertain spending mandate./ खर्च के जनादेश का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट।
- Elections should be held within six months from the date of supersession, if any/ यदि कोई हो, तो पद से हटाने की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए।
- Minister for Panchayati raj in the state council of ministers./ राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री।
- Reservation of Seats for SCs and STs on the basis of their population./ उनकी आबादी के आधार पर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण।
- Constitutional recognition should be accorded to the PRIs, which will ensure sanctity and stature and an assurance of continuous functioning./ PRI को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे पवित्रता और कद सुनिश्चित होगा और लगातार काम करने का आश्वासन मिलेगा।

G. V. K. Rao committee (1985)

- Committee to review the existing "Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes"./ मौजूदा "ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था" की समीक्षा करने वाली समिति।
- Zilla Parishad (District level body) should be of pivotal importance in the scheme of democratic decentralisation./ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद (जिला स्तर का निकाय) का मुख्य महत्व होना चाहिए।
- A post of District Development Commissioner should be created. He should act as the chief executive officer of the Zilla Parishad and should be in charge of all the development departments at the district level./ जिला विकास आयुक्त का एक पद बनाया जाना चाहिए। वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और जिला स्तर पर सभी विकास विभागों का प्रभारी होगा।
- Regular elections to the Panchayati Raj institutions/ पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव

L M Singhvi Committee (1986)

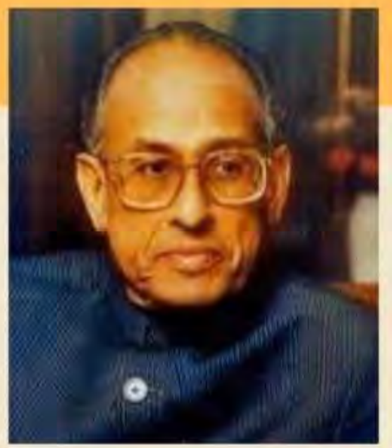

- In 1986, Rajiv Gandhi Government appointed a committee to prepare a concept paper on 'Revitalisation of Panchayati Raj Institutions for democracy and development' under the chairmanship of L.M Singhvi./ 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को फिर से मज़बूत बनाने' पर एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की।

Recommedations/ सिफारिशें :

- The panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized , protected and preserved./ पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।
- Nyaya Panchayat should be established for a cluster of villages./ गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।
- The village panchayats should have more financial resources./ ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
- Judicial tribunals should be established in each state to adjudicate controversies about election to the Panchayati Raj institutions, their dissolution and other matters related to their functioning./ पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, उनके भंग होने और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर विवादों का निपटारा करने के लिए हर राज्य में न्यायिक ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने चाहिए।

Gadgil committee (1988)

- Constitutional status should be bestowed on the Panchayati Raj institutions./ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- Three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block and district levels./ गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Fixed five years term of Panchayati Raj institutions./ पंचायती राज संस्थाओं का निश्चित पांच साल का कार्यकाल।
- Reservation for SCs, STs and women proportionate with their population./ SC, ST और महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण।
- Establishment of a State Finance Commission for the allocation of finances to the Panchayats./ पंचायतों को फाइनेंस के बंटवारे के लिए एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
- Establishment of a State Election Commission for the conduction of elections to the panchayats./ पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

73rd constitutional Amendment Act of 1992

- New part IX to the constitution, eleventh schedule consisting 29 functional items of the panchayats./ संविधान में नया भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं।
- Part IX: Article 243 To Article 243 O./ भाग IX: अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 O तक।
- Democratic shape to Article 40 (DPSP): "state to organise the village panchayats and provide them powers and authority so they can function as self-government."/ अनुच्छेद 40 (DPSP) को लोकतांत्रिक रूप देना: "राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करना होगा और उन्हें शक्तियां और अधिकार देने होंगे ताकि वे स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें।"
- The act has two parts: compulsory and voluntary./ इस अधिनियम के दो भाग हैं: अनिवार्य और स्वैच्छिक।
- Compulsory Provisions: must be added to state laws, which includes the creation of the new Panchayati Raj systems./ अनिवार्य प्रावधान: इन्हें राज्य कानूनों में जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है।
- Voluntary Provisions: on the other hand, are at the discretion of the state government./ स्वैच्छिक प्रावधान: दूसरी ओर, राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर हैं।

Motto

- Rural development is one of the main objectives of Panchayati Raj and this has been established in all states of India except Nagaland, Meghalaya and Mizoram, in all Union Territories except Delhi. and certain other areas.

These areas include

- The scheduled areas and the tribal areas in the states
- The hill area of Manipur for which a district council exists

Committees

- The committees appointed are as follows:

1. **Balwant Rai Mehta Committee**
2. **Ashok Mehta Committee**
3. **G V K Rao Committee**
4. **L M Singhvi Committee**

Gadgil

Balwant Rai Mehta Committee Recommendations

- Three-tier Panchayati Raj system: gram panchayat, Panchayati Samiti and Zila Parishad.
- Directly elected representatives to constitute the gram panchayat and indirectly elected representatives to constitute the Panchayat Samiti and Zila Parishad.
- Planning and development are the primary objectives of the Panchayati Raj system.
- Panchayat Samiti should be the executive body and Zila Parishad will act as the advisory and supervisory body.
- District collector to be made as the chairman of the Zila Parishad.
- It also requested for provisioning resources so as to help them discharge their duties and responsibilities.

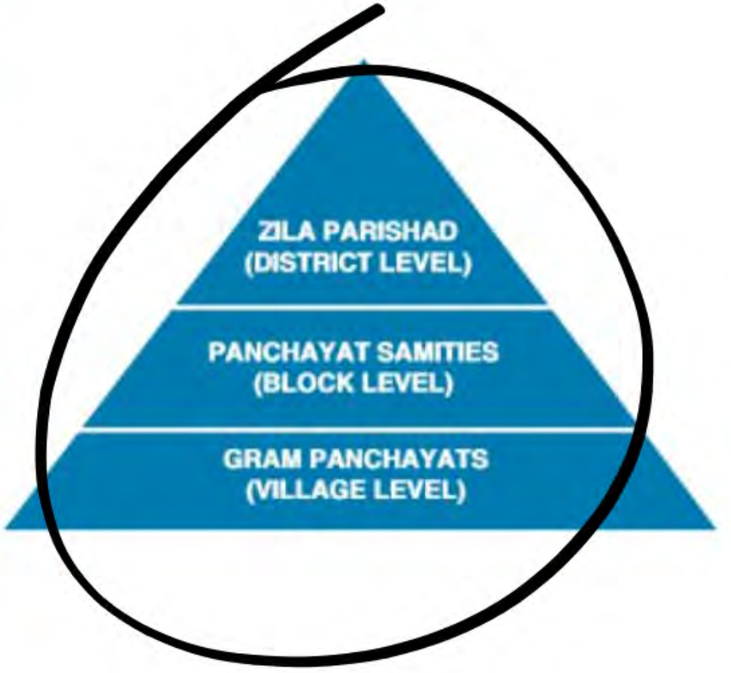

Some Facts

- It's a review process of CDP.
- Firstly Panchayati Raj System was established in Nagaur district of Rajasthan in 1959.
- In Constitution, it is named as "The Panchayat" .
- Article 243 and it's Sub-Parts describe about Panchayati Raj System.

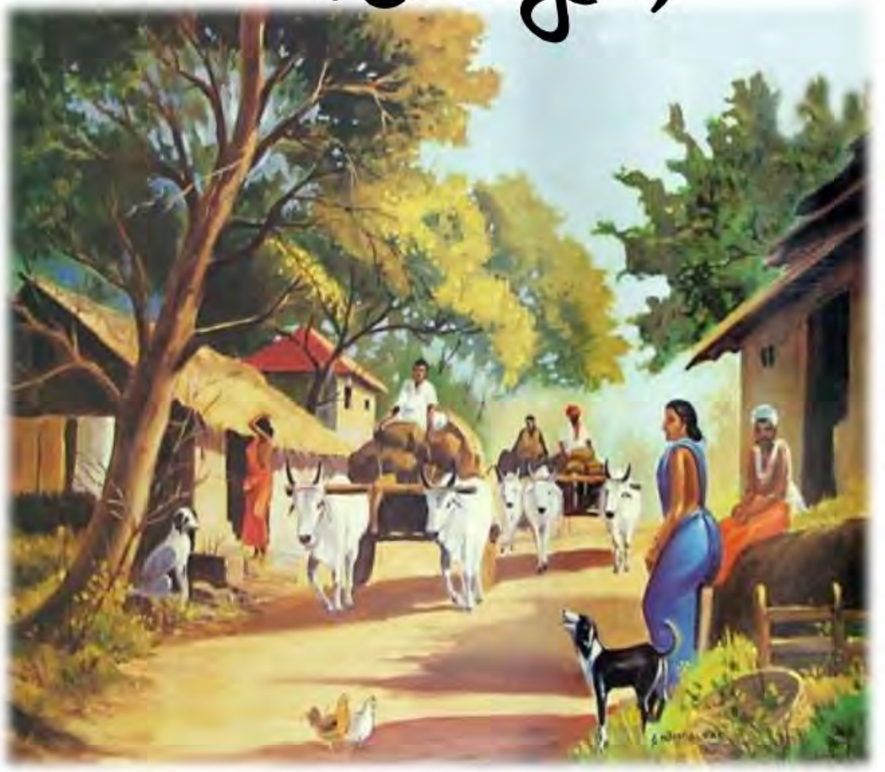

Articles related to Panchayati Raj System

- Article 243 A: There shall be a Panchayati Raj System.
- Article 243 B: There shall be a three tire Panchayati Raj System in all States.
- Article 243 C: Minimum age for election is 21 years old.
- Article 243 D: 1/3% Reserved seats for Women.

Varun Awasthi (GS Guru)

Articles related to Panchayati Raj System

- Article 243 E: Office Term- 5 years
- Article 243 F: Qualifications for Elections.
- Article 243 G: Powers of Panchayat like Works and schemes for villages, Social Justice etc.
- Article 243 H: Financial Authorities like tax collection, tolls and duties.
- Article 243 I: It describes that Governor will take a review every after five years of Panchayats in financial aspects.

Articles related to Panchayati Raj System

- Article 243 J: It gives right to Panchayat that they have to maintain and audit accounts in local levels.
- Article 243 K: Elections of Pachayat by State election commission.
- Article 243 L: Panchayats will apply in Union Territories also.

Varun Awasthi (GS Guru)

- Article 243 M: Panchayats will not apply in some Valley Areas of J&K, Nagaland, Sikkim, Manipur, Assam etc.

Articles related to Panchayati Raj System

- Article 243 N: Continuance of Existing Panchayat & Laws
- Article 243 O: Bar to interference by courts in electoral matters
- Nyaya Panchayats are the judicial components of the panchayat system, which forms the lowest rung of our judiciary. They are created for the administration of justice at the local or rural level. Reasons for setting up Nyaya Panchayats.

Varun Awasthi (GS Guru)

PESA Act of 1996

Objectives of PESA act

- To extend the provisions of part IX to the scheduled areas.
- To provide self-rule for the tribal population.
- To have village governance with participatory democracy
- To evolve participatory governance consistent with the traditional practices.
- To preserve and safeguard traditions and customs of tribal population.
- To empower panchayats with powers conducive to tribal requirements.
- To prevent panchayats at a higher level from assuming powers and authority of panchayats at a lower level.

States covered/ कवर किए गए राज्य

- **PESA applies to 10 states having fifth scheduled areas:**

पेसा 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों पर लागू होता है:

- ✓ Andhra Pradesh
- ✓ Chhattisgarh
- ✓ Gujarat
- ✓ Himachal Pradesh
- ✓ Jharkhand
- ✓ Madhya Pradesh
- ✓ Maharashtra
- ✓ Odisha
- ✓ Rajasthan
- ✓ Telangana

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243	• Definitions / परिभाषाएँ
Article 243A	• Gram Sabha / ग्राम सभा
Article 243B	• Constitution of Panchayats / पंचायतों का गठन
Article 243C	• Composition of Panchayats / पंचायतों की संरचना
Article 243D	• Reservation of seats / सीटों का आरक्षण
Article 243E	• Duration of Panchayats / पंचायतों की अवधि
Article 243F	• Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यता
Article 243G	• Powers, authority and responsibilities of Panchayats / पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व
Article 243H	• Powers to impose taxes by, and funds of the Panchayats / पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनके कोष
Article 243I	• Constitution of Finance Commission to review financial position / वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243J	• Audit of accounts of Panchayats / पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण
Article 243K	• Elections to the Panchayats / पंचायतों के चुनाव
Article 243L	• Application to Union Territories / संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
Article 243M	• Part not to apply to certain areas / कुछ क्षेत्रों पर यह भाग लागू नहीं होगा
Article 243N	• Continuance of existing laws and panchayats / विद्यमान कानूनों और पंचायतों की निरंतरता
Article 243O	• Bar to interference by courts in electoral matters / चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

Question : 1

Which part of the constitution deals with the Panchayats?

संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है?

Art. 243

(a) Part X / भाग X

(b) Part IX / भाग IX

(c) Part VII / भाग VII

(d) Part IV / भाग IV

(SSC CGL 23/09/2024)

Question : 2

Which of the following states is of those states that have no Panchayati Raj Institutions?

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से है जहाँ पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं?

(SSC CGL 25/09/2024)

(a) Punjab / पंजाब

(b) Gujarat / गुजरात

(c) Nagaland / नागालैंड

(d) Assam / असम

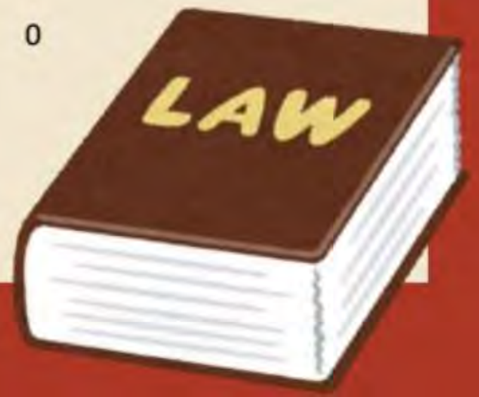

Question : 3

The election to constitute a Panchayat should be completed before the expiration of a period of __ from the date of its dissolution.

पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तिथि से __ की अवधि समाप्त होने से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए।

(a) Eight months / आठ महीने

(b) One year / एक वर्ष

(c) Six months / छह महीने

(d) Two months / दो महीने

(SSC CHSL 14/10/2020)

Question : 4

Article 243K of the constitution deals with which of the following?

संविधान का अनुच्छेद 243K निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) Duration of the Panchayat / पंचायत की अवधि

(b) Grounds of disqualification from membership of Panchayat / पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के आधार

(c) Reservation of seats in Panchayat / पंचायत में सीटों का आरक्षण

(d) Election to the Panchayat / पंचायत के चुनाव

By State EC

(SSC CHSL 20/03/2023)

Question : 5

A Panchayat continue for ___ from the date appointed for its first meeting.

पंचायत अपनी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से ___ तक कार्य करती है।

(a) 14 years

(b) 11 years

(c) 5 years

(d) 9 years

(SSC MTS 18/10/2021)

Question : 6

The elections to the Panchayati Raj Institutions are conducted by the ___

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ___ द्वारा कराए जाते हैं।

(a) Central Election Commission / केंद्रीय चुनाव आयोग

(b) State Government / राज्य सरकार

(c) State Election Commission / राज्य चुनाव आयोग

(d) Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग

(SSC CGL 2020)

Question : 7

When was the third tier added to Indian Federal System?

भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया था?

(a) 1990

(b) 1991

(c) 1992

(d) 1993

(UPPCS 2020)

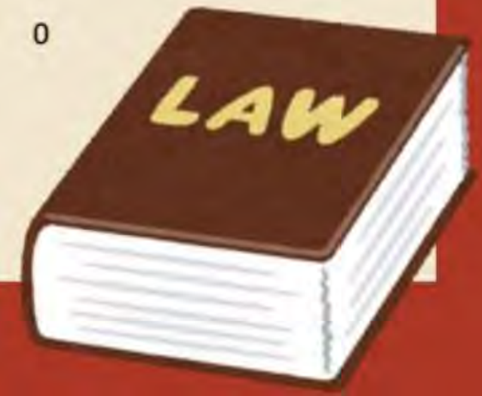

Question : 8

Which Article gives the list of 29 functions to be performed by the Panchayati Raj Institutions?

कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची प्रदान करता है?

(a) Article 243(H)

(b) Article 243(E)

(c) Article 243(F)

(d) Article 243(G)

(BPSC PRE 2020)

Question : 9

Which of the following is not a part of the Eleventh Schedule of the constitution?

निम्नलिखित में से कौन संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची का भाग नहीं है?

(a) Libraries / पुस्तकालय

(b) Fuel and fodder / ईंधन और चारा

(c) Rural sports / ग्रामीण खेल

(d) Technical training / तकनीकी प्रशिक्षण

(BPSC PRE 2022)

Question : 10

The reservation of seats for women in Panchayats has been provided by an amendment to constitution of India. That amendment is _

पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय संविधान में एक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। वह संशोधन है _

(a) 70th amendment of 1992 / 1992 का 70वां संशोधन

(b) 73rd amendment of 1992 / 1992 का 73वां संशोधन

(c) 74th amendment of 1992 / 1992 का 74वां संशोधन

(d) 77th amendment of 1994 / 1994 का 77वां संशोधन

(RAS PRE)